अतारांकित-*03*

(क) राज्य सरकार निवेश आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गई।

निवेशोन्मुख नीति एवं उत्तर प्रदेश को विश्व स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गन्तव्य के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष-2018 में ''यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट'' का आयोजन किया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैड्स, फिनलैण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य तथा स्लावाकिया आदि देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों ने उक्त निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
(ख) निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देश-विशिष्ठ समर्पित हेल्प-डेस्क स्थापित किये गये। जिसके परिणामस्वरूप उक्त देशों की अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा राज्य में निवेश किया गया है, जो निम्नवत है:-

1. अमेरिका का एमएक्यू साफ्टवेयर 252 करोड रूपये का निवेश कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गौतमबुद्धनगर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट परियोजना की स्थापना के लिए 1800 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
2. यूनाइटेड किंगडम की एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स(एबी मौरी) द्वारा पीलीभीत में खमीर उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए 1,100 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
3. जर्मनी की वान वेलक्स ने आगरा में फुटवियर निर्माण परियोजना की स्थापना के लिए 300 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
4. दक्षिण कोरिया की समकवांग द्वारा 300 करोड रूपये का निवेश, ड्रीमटेक इलेक्ट्रानिक्स द्वारा 265 करोड रूपये का निवेश स्टारियन द्वारा गौतमबुद्धनगर में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण परियोजना की स्थापना के लिए 400 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
5. सिंगापुर की एसटीटी जीडीसी इंडिया द्वारा गौतमबुद्धनगर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 900 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
6. जापान की एनटीटी नेटमैजिक द्वारा गौतमबुद्धनगर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 1500 करोड रूपये का निवेश, एलाइड निप्पान द्वारा गौतमबुद्धनगर में आटो कंपोनेंट्स निर्माण परियोजना की स्थापना के लिए 240 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।
7. फ्रांस की एयर लिक्विड द्वारा मथुरा में एयर सेपरेशन/आक्सीजन उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए लगभग 350 करोड रूपये का निवेश किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'

मंत्री

औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग।